4 एस.सी.आर. 521

नूर खान

बनाम

राजस्थान राज्य

(न्यायमूर्तिगण ए. के. सरकार, एम. हिदायतुल्ला और जे. सी. शाह)

आपराधिक मुकदमा–हत्या–ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषमुक्ति–उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति को रद्द करने के बाद दोषसिद्धि–वैधता–पुलिस द्वारा गवाहों के बयानों के रिकॉर्ड से संबंधित प्रावधान और अभियुक्तों को प्रतियां प्रदान करने में विफलता–यदि और कब मुकदमा खराब होता है–पूर्वाग्रह –दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का अधिनियम 5) । उपधारा 161(3), 162, 173(बी), 207 ए(3)।

अपीलकर्ता और नौ अन्य लोगों पर दंगा करने, गैरकानूनी जमावड़े का सदस्य होने और अपने सामान्य उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति की मौत और चार अन्य को गंभीर चोटें पहुंचाने के अपराध के लिए सत्र न्यायाधीश के समक्ष मुकदमा चलाया गया। अपीलकर्ता पर बंदूक की गोली से मौत का गंभीर अपराध करने का भी आरोप लगाया गया था। मुकदमे में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। राज्य द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ अपील में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बाकी के संबंध में आदेश की पुष्टि की। इस अदालत में अपीलकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत एक जांच अधिकारी के लिए उसके द्वारा जांचे गए गवाहों के बयान दर्ज करना अनिवार्य है और यदि वे बयान मुकदमे में आरोपी को उपलब्ध नहीं कराए गए थे, अभियुक्त के लिए एक मूल्यवान अधिकार खो गया था, और केवल उस कारण से मुकदमे को दूषित माना जाना चाहिए।

अभिनिर्धारित किया गया: (i) जहां परिस्थितियां ऐसी हैं कि अदालत उचित अनुमान लगा सकती है कि धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों को प्रदान करने में विफलता के कारण अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है, अदालत को यह निर्देश देना उचित होगा कि दोषसिद्धि को खारिज कर दिया जाए और उचित तरीके से यह निर्देश दे कि दोष को परिस्थितियों के अनुसार ठीक किया जाए। यह केवल तभी होता है जब अदालत इस बात से संतुष्ट होती है कि मामले को जिस तरीके से चलाया गया है और दोष के संबंध में आरोपी द्वारा अपनाए गए रवैये को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं हुआ है और अदालत वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के बावजूद दोषसिद्धि को बरकरार रखने में न्यायसंगत हो सकती है।

वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा और पूर्वाग्रह की दलील न तो उच्च न्यायालय में उठाई गई, न ही इस न्यायालय में इसके समर्थन में कोई ठोस तर्क दिया गया।

नारायण राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ए आई आर 1957 एस सी 737 और पुलुकुरी कोटय्या बनाम सम्राट, एल आर 74 आई ए 65 पर भरोसा किया गया।

बलिराम बनाम सम्राट, आईएलआर [1945] नाग। 151, मगनलाल बनाम सम्राट, आईएलआर [1946] नाग। 126 और मारोती महगू बनाम सम्राट, आईएलआर [1948] नाग। 110, अस्वीकृत.

(ii) वर्तमान मामले में सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के आचरण पर अपना निष्कर्ष नहीं निकाला और उच्च न्यायालय ने सही कहा कि अपराध स्थल पर चार घायल व्यक्तियों की उपस्थिति चोटों के साक्ष्य द्वारा सुनिश्चित की गई थी, और संदेह से परे स्थापित माना जाएगा।

शेओ स्वरूप बनाम राजा सम्राट, एल आर 61 आईए 398, का उल्लेख किया गया है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1963 की आपराधिक अपील संख्या 9।

डीबी क्रिमिनल अपील संख्या 407/1961 में राजस्थान उच्च न्यायालय के 9 नवंबर, 1962 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ता की ओर से पुरूषोत्तम त्रिकमदास, सी, एल सरेन और आर एल कोहली।

प्रतिवादी की ओर से एस के कपूर और आर एन सच्ते।

19 अगस्त, 1963. न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

राजस्थान राज्य के कुचामन के निवासी शाह जे–नूर खान और नौ अन्य पर दंगा करने और गैरकानूनी सभा का सदस्य होने और उनके सामान्य कार्यों को आगे बढ़ाते हुए लगभग 2–30 पी एम, 29 सितम्बर 1960 को एक प्रताप की मृत्यु और उसी अवसर पर चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल करने के अपराध के लिए राजस्थान राज्य के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिरोही के समक्ष मुकदमा चलाया गया। नूर खान पर भी बंदूक की गोली से प्रताप की मृत्यु का गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया था। सत्र न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। परीक्षण में. राज्य की अपील में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने नूर खान के पक्ष में बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया और बाकी के संबंध में आदेश की पुष्टि की।

मुंडारा गांव में एक कुएं को लेकर एक तरफ नूर खान और दूसरी तरफ प्रताप और उसके भाइयों के बीच विवाद थे। नूर खान ने दावा किया कि उन्होंने कुएं में आधा हिस्सा खरीदा है, जबकि प्रताप और उनके भाइयों ने दावा किया कि यह कुआं उनकी विशेष संपत्ति है, और इस विवाद को लेकर कई अदालती कार्यवाही भी हुईं। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 29 सितंबर, 1960 को लगभग 2–00 बजे। नूर खान अपने पिता समदू खान और आठ अन्य लोगों के साथ प्रताप के पास गए। खेत (जिसमें एक खेत, एक घर, एक अस्तबल और विवादित कुआँ था) और कुएँ पर कब्ज़ा देने के लिए प्रताप को बुलाया और ऐसा करने से इनकार करने पर, समदू खान ने गणेश पर थूथन–लोडिंग बंदूक से गोली चला दी–– प्रताप का भाई–लेकिन उससे चूक गया। नूर खान ने तब प्रताप पर गोली चलाई और उसे तुरंत मार डाला। इसके बाद समदू खान की शह पर नूर खान की पार्टी के अन्य सदस्यों ने प्रताप के भाइयों गणेश, प्रभु, मोहन और गुलाब को लाठियों और अन्य हथियारों से पीटा और उन्हें घायल कर दिया। हमलावरों के सेवानिवृत्त होने के बाद, गणेश ने पुलिस स्टेशन, बाली में नूर खान और समदू खान सहित 15 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में नामित लोगों में से दस को गिरफ्तार कर लिया गया और सत्र न्यायालय, सिरोही के समक्ष उन पर मुकदमा चलाया गया। सत्र न्यायाधीश ने यह कहते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया कि यह कहानी कि दस या अधिक व्यक्तियों की एक गैरकानूनी सभा थी जो कुएं पर गई और प्रताप की मौत का कारण बनी, विश्वसनीय नहीं थी, क्योंकि उनके विचार में अभियोजन पक्ष स्वतंत्र साक्ष्य देने में विफल रहा था। अभियोजन पक्ष की कहानी में समय–समय पर गवाहों और बदलाव किए गए और कुछ व्यक्तियों को गलत तरीके से शामिल किया गया। उन्होंने देखा कि दोनों पक्षों के बीच

दुश्मनी थी और गवाहों की गवाही, जिन्होंने हमले के स्थान पर मौजूद होने का दावा किया था, स्वतंत्र सबूतों से पुष्ट नहीं हुई और यह श्रेय के योग्य नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि शिकायतकर्ता गणेश ने कई लोगों का नाम लिया था। जिनके बारे में यह साबित हो गया कि उन्होंने हमले में हिस्सा नहीं लिया था।

राज्य की अपील में, राजस्थान के उच्च न्यायालय ने नूर खान को मज़ल–लोडिंग बंदूक से गोली चलाकर और उसे घातक चोट पहुंचाने के कारण प्रताप की मौत का दोषी ठहराया और इस तरह धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध किया और उसे कारावास की सजा सुनाई। जीवन के लिए। विशेष अनुमति के साथ नूर खान ने इस अदालत में अपील की है.

29 सितम्बर, 1960 को गोली लगने के कारण प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. मेहता की गवाही से पता चलता है कि प्रवेश के घाव के अलावा पीड़ित का बायां फेफड़ा धातु के टुकड़ों से जख्मी हो गया था। डॉ. मेहता ने गवाह प्रभु के शरीर पर दो खरोंच और एक कटी हुई चोट पाई, गणेश के शरीर पर तीन चोट के निशान, मोहन के शरीर पर एक चोट और गुलाब के शरीर पर एक सूजन पाई और डॉ. मेहता के अनुसार, जब उन्होंने जांच की तो ये चोटें थीं। 1 अक्टूबर 1960 को घायल व्यक्ति, लगभग 48 घंटे पुराने। प्रभु, गणेश, मोहन और गुलाब से अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में पूछताछ की गई, और उन्होंने बताया कि नूर खान ने प्रताप पर मज़ल–लोडिंग बंदूक से गोली चलाकर उसे घातक चोट पहुंचाई थी, और सदस्यों द्वारा उसी घटना में वे घायल हो गए थे। नूर खान की पार्टी का. इन चारों व्यक्तियों की चोटें उनकी कहानी को दृढ़ता से पुष्ट करती हैं कि हमले के समय लगभग 2–00 बजे प्रताप पर हमला किया गया था। 29 सितम्बर 1960 को वे उपस्थित थे। इस कहानी को दो महिला गवाहों, भंवरी और मथुरा ने और भी पुष्ट किया।

राज्य द्वारा अपील में उच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन मामले में कमजोरियों के बावजूद, पहली सूचना में, कुछ व्यक्तियों के नाम जो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, शिकायतकर्ता गणेश द्वारा दुश्मनी के कारण दिए गए थे और वहां थे मुकदमे में चश्मदीद गवाहों के बयानों और इस सवाल पर पहली जानकारी के बीच विसंगतियां कि दो व्यक्तियों समदु खान और अपीलकर्ता नूर खान में से किसने पहले गोली चलाई, अभियोजन का महत्वपूर्ण मामला अप्रभावित रहा, प्रत्येक के लिए चार चश्मदीद गवाहों में से गणेश, प्रभु, मोहन और गुलाब के शरीर पर चोटों के निशान थे, जिसकी अवधि जब डॉ. मेहता द्वारा जांच की गई तो उनकी कहानी से मेल खाती थी और चोटों की उपस्थिति ने उनकी गवाही को आश्वस्त किया कि वे घटना के समय मौजूद थे, और स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति अपने आप में उन गवाहों की गवाही को खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं थी जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने प्रताप पर हमला होते देखा था। सुश्री की गवाही पर भरोसा करते हुए। भंवरी 'मोहन सिंह और सुश्री की गवाही द्वारा समर्थित. मथुरा उच्च न्यायालय ने माना कि यह घातक चोट है। अपीलकर्ता द्वारा प्रताप के शरीर से लगभग 4 फीट की दूरी से बंदूक से गोली चलाई गई।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध थी। लेकिन जैसा कि शेओ स्वरूप और अन्य बनाम राजा सम्राट (1) में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा समझाया गया है: "संहिता के एसएस, 417, 418 और 423 उच्च न्यायालय को बड़े पैमाने पर उन सबूतों की समीक्षा करने की पूरी शक्ति देते हैं जिन पर बरी करने के आदेश को गोल कर दिया गया, और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि उस साक्ष्य के आधार पर बरी करने के आदेश को उलट दिया जाना चाहिए। * * * * *

लेकिन संहिता द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने में और तथ्य पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, उच्च न्यायालय को हमेशा ऐसे मामलों पर उचित महत्व और विचार करना चाहिए और विचार करना चाहिए (1)

गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में ट्रायल जज के विचार; (2) अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा, एक धारणा निश्चित रूप से इस तथ्य से कमजोर नहीं हुई है कि उसे अपने मुकदमे में बरी कर दिया गया है; (3) किसी भी संदेह के लाभ के लिए अभियुक्त का अधिकार; और (4) एक न्यायाधीश द्वारा निकाले गए तथ्य के निष्कर्ष को परेशान करने में अपीलीय न्यायालय की सुस्ती, जिसे गवाहों को देखने का लाभ मिला था। हमले को देखते हुए, सत्र न्यायाधीश ने इस महत्वपूर्ण परिस्थिति के पूर्ण महत्व की सराहना नहीं की कि चार चश्मदीद गवाहों के शरीर पर चोटें थीं जो चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार उस समय या उसके आसपास हुई होंगी जब घातक हमला हुआ था। यह अत्यधिक असंभव है कि ये सभी गवाह जो एक ही परिवार के सदस्य थे, उन्हें उस दिन और उसी समय किसी अन्य घटना या घटना में चोटें लगीं, जिनमें से कुछ गंभीर थीं, जब प्रताप घातक रूप से घायल हुए थे। और फिर उन्होंने झूठी गवाही देने की साजिश रची कि वे प्रताप पर हमले के समय वहां मौजूद थे। अपराध स्थल पर चार घायल व्यक्तियों गणेश, प्रभु, मोहन और गुलाब की उपस्थिति चोटों के साक्ष्य से सुनिश्चित होती है, और होनी चाहिए जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा, उचित संदेह से परे स्थापित माना जाना चाहिए।

सत्र न्यायाधीश ने संभवतः गणेश को छोड़कर, गवाहों के आचरण पर अपना निष्कर्ष नहीं निकाला। उन्होंने साक्ष्यों की समीक्षा की और अपने निष्कर्ष को मुख्य रूप से चार परिस्थितियों पर आधारित किया:

(i) जो व्यक्ति अपराध के समय उपस्थित नहीं थे, उन्हें अपराध में शामिल करने की मांग की गई थी;

(ii) सबूतों से पता चला कि केवल एक ही गोली चलाई गई थी, जबकि गवाहों ने गवाही दी थी कि समदू खान और नूर खान दोनों थूथन–लोडिंग बंदूकों से लैस थे और हमले के समय उनका इस्तेमाल किया था;

(iii) गवाहों ने अनुमान लगाया था कि जिस बंदूक से प्रताप को घातक चोट लगी थी, वह दूरी 20 फीट से कम नहीं थी, जबकि डॉ. मेहता ने कहा था कि बंदूक केवल 4 फीट की दूरी से चलाई गई थी।

(iv) आरोपी नूर खान और अन्य को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए पुलिस बयानों तक पहुंच के लाभ से वंचित किया गया था।

पहली सूचना में दो व्यक्तियों नरपत सिंह और प्रताप सिंह पर उस पक्ष के सदस्य होने का आरोप लगाया गया था जो नूर खान और समदु खान के साथ अपराध स्थल पर पहुंचे थे, ऐसी स्थिति है जिसके लिए अदालत को उनकी गवाही की जांच करने की आवश्यकता हो सकती है। गणेश ने बड़े ध्यान से मुखबिरी की. लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में गणेश की गवाही पर भरोसा नहीं किया; उस गवाही को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था, और उस गवाही के बारे में और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस थाने में दर्ज प्रथम सूचना में नूर खान की पार्टी के सदस्यों के रूप में नरपत सिंह और प्रताप सिंह के नाम शामिल होने से, हालांकि, अन्य गवाहों की गवाही पर कोई संदेह नहीं होता है जिन्होंने उन्हें आयोग में शामिल करने का प्रयास नहीं किया था। अपराध का. सत्र न्यायाधीश ने यह भी माना कि दो अन्य व्यक्तियों केसिया चौधरी और श्योनाथ सिंह का भी पहली सूचना में नाम लिया गया था, हालांकि वे अपराध स्थल पर मौजूद नहीं थे। गणेश ने जब जिरह की तो स्वीकार किया कि ये दोनों व्यक्ति प्रताप पर हमले के बाद अपराध स्थल पर पहुंचे थे और अन्य गवाहों ने यह नहीं बताया कि उन्होंने हमले के समय उन्हें देखा था। तथ्य यह है कि गणेश द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के अनुसार कुछ लोग उस समय उपस्थित नहीं थे जब नूर खान की पार्टी घटनास्थल पर पहुंची, गणेश की गवाही की विश्वसनीयता के बारे में गंभीर संदेह पैदा हो सकता है, लेकिन यह अपने आप में नहीं होगा

अन्य गवाहों की कहानी को खारिज करने का आधार बनें। यह सच है कि गवाह प्रभु सिंह पुत्र गुमान सिंह, जो परिवार का सदस्य नहीं था और जिसने प्रताप और अन्य पर हमले का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया था, पूरी तरह से अविश्वसनीय पाया गया और एक अन्य व्यक्ति को गवाह के रूप में उद्धृत किया गया। सोहन सिंह, जो परिवार का सदस्य भी नहीं था, से मुकदमे में पूछताछ नहीं की गई। लेकिन जिस स्थान और समय पर अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया है, वह ऐसा था कि ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति की कम से कम उम्मीद की जा सकती थी जो प्रताप के करीबी रिश्तेदार नहीं थे।

सभी चश्मदीदों ने लगातार यह बयान दिया है कि नूर खान ने ही प्रताप को घातक चोट पहुंचाई थी। गवाहों के साक्ष्य के अनुसार, हमले के समय नूर खान और समदू खान दोनों थूथन–लोडिंग बंदूकों से लैस थे, और प्रताप के शरीर पर केवल एक बंदूक की गोली का घाव पाया गया है। गवाहों द्वारा यह बताया गया कि समदू खान ने अपने पास रखी बंदूक से गणेश पर गोली चलाई थी, लेकिन गोली गणेश को नहीं लगी। लेकिन गणेश के शरीर पर बंदूक की गोली की चोट का अभाव पूरी कहानी को स्वाभाविक रूप से इतना असंभव नहीं बनाता है कि इसे अविश्वसनीय मानकर खारिज कर दिया जाए। न ही पहली सूचना और अदालत में गवाही के बीच गोलीबारी के अनुक्रम के संबंध में विसंगति, उस पाठ्यक्रम के समर्थन में कोई उचित आधार प्रस्तुत करती है।

नूर खान द्वारा जिस दूरी से घातक गोली चलाई गई थी, उसके बारे में गवाहों द्वारा दिए गए अनुमानों में विसंगति है। प्रत्यक्षदर्शियों ने अनुमान लगाया है कि यह दूरी 8 से 15 पाउंड के बीच है – प्रत्येक पाउंड 'एक कदम' या दो फीट के बराबर है। हालाँकि, चोट की उपस्थिति और विशेष रूप से प्रवेश के घाव के जलने और काले पड़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि बंदूक की बैरल 3 या 4 फीट से अधिक की दूरी पर नहीं हो सकती थी। लेकिन जैसा कि हम वर्तमान में इंगित करेंगे, अनुमान दिया गया है गवाहों द्वारा, स्थलाकृति और जिन परिस्थितियों में हमला हुआ था, के प्रकाश में जांच की गई, अशिक्षित और अर्ध–साक्षर ग्रामीणों के अनुमानों को अनुचित महत्व देने की आवश्यकता नहीं होगी। सत्र न्यायाधीश का निर्णय इस कमज़ोरी से ग्रस्त है कि अपराध स्थल पर कुछ निश्चित स्थितियों के आलोक में गवाहों के साक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किए बिना, और एक स्केल मानचित्र को सुरक्षित करने का प्रयास किए बिना, उन्होंने कहानी को खारिज कर दिया। पाउंड के संदर्भ में बताई गई दूरियों के अनुमान में विसंगति के कारण गवाह। अपराध स्थल पर कुछ निश्चित वस्तुएँ थीं जैसे पीपल का पेड़, ओरा (कमरा), ढालिया (स्थिर), फालसा (बाड़ में खुला), कुआँ और चबूतरा (चबूतरा)। यदि गवाहों के साक्ष्य की जांच न केवल दूरी के बारे में गवाहों के अनुमान के आधार पर की जाती है, खासकर अनपढ़ या अर्ध–साक्षर गवाहों के मामले में तो यह बेहद अविश्वसनीय है, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि सत्र न्यायाधीश ने जो निष्कर्ष निकाला है। था .पहुंचने के लिए राजी किया गया स्वीकार नहीं किया जा सकता.

नूर खान द्वारा जिस दूरी से बंदूक चलाई गई बताई गई है, उसके बारे में गवाहों का अनुमान अलग–अलग है। गणेश ने बताया कि दूरी लगभग 20 फीट थी। अन्य गवाहों ने अनुमान लगाया कि दूरी लगभग 8 से 15 पाउंड थी। गौर करने वाली बात यह है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार वहां लगभग दस व्यक्ति मौजूद थे। उनमें से दो बंदूकों से लैस थे, कुछ कुल्हाड़ियों से और बाकी लाठियों से लैस थे। उन्होंने खुद को खेत के उस छोटे से क्षेत्र में फैला लिया होगा जहां कुआं, ओरा और ढालिया स्थित हैं। गवाहों की लगातार गवाही से ऐसा प्रतीत होता है कि हमला करने वाला पक्ष हमले के समय पीपल के पेड़ के पास कहीं था, जिसकी स्थिति निश्चित रूप से विश्वसनीय सबूतों से स्थापित होती है, जो कि पीपल के पेड़ से लगभग 8 फीट की दूरी पर थी। ओरा की दीवार का पश्चिमी छोर। नूर खान ने जिस बंदूक का इस्तेमाल किया था वह एक थूथन–लोडिंग बंदूक थी और

बैरल की लंबाई 5 फीट थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों की पार्टी पीपल के पेड़ से आगे नहीं बढ़ी थी और जैसा कि एमएसटी ने कहा था। भंवरी. जिस पर विश्वास किया गया है. उच्च न्यायालय ने गवाहों द्वारा इसकी पुष्टि की। मथुरा और मोहन सिंह, ऐसा प्रतीत होता है कि नूर खान पीपल के पेड़ के पास था, यह अनुमान अपरिहार्य है कि बैरल के अंत और प्रताप के बीच की दूरी 4 फीट से अधिक नहीं थी। प्रवेश के एक बिंदु पर बंदूक स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि बंदूक को करीब से गोली मारी गई थी। ओरा, ढालिया और पीपल के पेड़ की स्थिति के आलोक में देखे गए गवाहों के साक्ष्य, जैसा कि रफ स्केच प्रदर्शनी पी–2 (ए) में दिखाया गया है, यह भी बताता है कि गवाहों द्वारा दूरी का अनुमान लगाया गया है प्रताप की ओर से हमलावर को स्वीकार नहीं किया जा सकता. एमएसटी. भंवरी ने कहा है कि नूर खान समदू खान से एक कदम की दूरी पर था और जब वे पीपल के पेड़ के पास थे तो समदू खान और नूर खान ने फायरिंग की थी. प्रभु ने नूर खान और प्रताप के बीच की दूरी का अनुमान 10 कदम बताया है, लेकिन सबूत से पता चलता है कि नूर खान ने ओरा के सामने एक जगह से गोली चलाई थी। गुलाब ने बताया कि समदू खां उससे पांच पौंड की दूरी पर खड़ा था और प्रताप उसके पास बैठा हुआ था। ओरा. मोहन ने गवाही दी कि पीपल का पेड़ 6 या 7 फीट की दूरी पर है, और आरोपी व्यक्ति पीपल के पेड़ के पूर्व की ओर और "ढलिया के केंद्र के सामने" थे। एमएसटी. मथुरा ने कहा है कि आरोपी पीपल के पेड़ के पीछे आये थे। प्रत्येक गवाह ने यह बयान दिया है कि प्रताप ओरा विला से एक कदम की दूरी पर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे थे, जिस दिशा में पीपल का पेड़ खड़ा था। सबूतों के इस विश्लेषण से पता चलता है कि नूर खान ने ओरा के दक्षिण में, पीपल के पेड़ के पास, प्रताप पर अपनी बंदूक चलाई, जो ओरा के विलाप से लगभग 2 फीट की दूरी पर बैठा था। उच्च न्यायालय ने सुश्री की गवाही स्वीकार कर ली। भंवरी ने एमएसटी की गवाही से पुष्टि की। मथुरा और मोहन सिंह और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इन तीन गवाहों ने ऐसी स्थिति के बारे में गवाही दी है जो चिकित्सा गवाही के अनुरूप है। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य चश्मदीदों की गवाही झूठी है, बल्कि यह केवल अनपढ़ ग्रामीणों द्वारा दी गई दूरी के गलत अनुमान का खुलासा करती है।

लेकिन मुकदमे में सबसे महत्वपूर्ण दोष, अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए श्री पुरूषोत्तम द्वारा आग्रह किया गया था, जो दोषसिद्धि के आदेश को ख़राब करता है, वह यह है कि आरोपी व्यक्तियों को गवाहों द्वारा दिए गए बयानों की प्रतियां प्राप्त करने और उपयोग करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। जांच अधिकारी हरि सिंह से पहले, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने गवाहों के बयानों के 'जोटिंग' या नोट्स बनाए थे, और उन्होंने जांच के दौरान विस्तृत बयान दर्ज नहीं किए थे, और इन 'जोटिंग्स' से हेड–कांस्टेबल कपूराराम ने गवाहों के बयान तैयार किए (मुकदमे के दौरान आरोपी को दिए गए) जब गवाह पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं थे। जिन गवाहों ने हमले को देखने का दावा किया था, उन्होंने अपनी जिरह में कहा कि कपूराराम द्वारा दिए गए कुछ बयान उनके द्वारा नहीं दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने पाया कि चूंकि बयान कपूराराम द्वारा 'जोटिंग्स' से लिखे गए थे, इसलिए उन बयानों से कोई मूल्य नहीं जोड़ा जा सकता था और जिन गवाहों ने कपूराराम द्वारा तैयार किए गए रिकॉर्ड में पाए गए बयानों के कुछ हिस्सों को देने से इनकार किया था, उनकी गवाही नहीं दी जा सकती थी। इसे अविश्वसनीय बनाओ। जांच अधिकारी हरि सिंह के साक्ष्य पर, जिन बयानों की प्रतियां अभियुक्तों को धारा 161 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किए गए बयानों की प्रतियां होने का दावा किया गया था, वे वास्तव में ऐसे बयान नहीं थे, और उच्च न्यायालय ने यह देखने में सही किया था उन बयानों और मुकदमे में गवाहों द्वारा दिए गए सबूतों के बीच विसंगतियां बचाव पक्ष की इस दलील का समर्थन नहीं करेंगी कि मुकदमे में दिया गया संस्करण अविश्वसनीय था, एक बाद के विचार के रूप में। लेकिन यह आग्रह किया गया कि धारा 161 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक जांच अधिकारी के लिए उसके द्वारा जांचे गए गवाहों के बयान दर्ज करना अनिवार्य है और यदि उन बयानों को मुकदमे में आरोपी को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह एक मूल्यवान अधिकार है जिसे

विधानमंडल ने सुनिश्चित किया है। मामले की संतोषजनक सुनवाई के हित में यदि मामला अभियुक्त से हार जाता है, तो केवल उसी आधार पर मुकदमे को दूषित माना जाना चाहिए।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी Ch के तहत जांच कर रहा है। XIV को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होने वाले किसी भी व्यक्ति की मौखिक रूप से जांच करने के लिए अधिकृत किया गया है। जिस व्यक्ति की जांच की जा रही है, वह ऐसे अधिकारी द्वारा उससे पूछे गए मामले से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य है, उन प्रश्नों के अलावा जिनके उत्तर उसे आपराधिक आरोप या जुर्माना या जब्ती के लिए उजागर करने की प्रवृत्ति रखते हैं। धारा 161 की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि एक पुलिस अधिकारी इस धारा के तहत जांच के दौरान दिए गए किसी भी बयान को लिख सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो उसे बयान का एक अलग रिकॉर्ड बनाना होगा। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जिसका बयान वह दर्ज करता है। 1955 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 26 द्वारा संशोधित संहिता की धारा 162 प्रदान करती है:

> "इस अध्याय के तहत जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान, यदि लिखित रूप में दर्ज किया गया है, तो इसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा; न ही ऐसा कोई बयान या उसका कोई रिकॉर्ड, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या अन्यथा, या इस तरह के बयान या रिकॉर्ड के किसी भी हिस्से का उपयोग उस समय जांच के तहत किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी उद्देश्य (इसके बाद दिए गए अनुसार को छोड़कर) के लिए किया जा सकता है जब ऐसा बयान दिया गया था:"

परंतुक द्वारा यह अधिनियमित किया गया है कि जब किसी गवाह को ऐसी जांच या मुकदमे में अभियोजन पक्ष के लिए बुलाया जाता है, जिसका बयान पूर्वोक्त रूप से लिखित रूप में कम कर दिया गया है, तो उसके बयान का कोई भी हिस्सा, यदि विधिवत साबित हो, आरोपी द्वारा उपयोग किया जा सकता है, और साथ में अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसे गवाह का खंडन करने के लिए न्यायालय की अनुमति।

1955 के अधिनियम 26 द्वारा संशोधित उपधारा (4) द्वारा संहिता की धारा 173 में यह प्रावधान है कि पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, जांच या परीक्षण शुरू होने से पहले, आरोपी को प्रदान करेगा या कराएगा। अन्य बातों के अलावा, धारा 154 के तहत दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट और अन्य सभी दस्तावेजों या उसके प्रासंगिक उद्धरणों की एक प्रति, जिस पर अभियोजन पक्ष भरोसा करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें धारा 161 की उप–धारा (3) के तहत दर्ज किए गए सभी बयान शामिल हैं। जिन व्यक्तियों की अभियोजन पक्ष प्रथम गवाह के रूप में जांच करने का प्रस्ताव करता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 ए जो 1955 के अधिनियम 26 द्वारा उपधारा (3) द्वारा जोड़ी गई है, प्रदान करती है:

> "जांच के प्रारंभ में, मजिस्ट्रेट, जब आरोपी उपस्थित होता है या उसके सामने लाया जाता है, तो खुद को संतुष्ट करेगा कि धारा 173 में निर्दिष्ट दस्तावेज आरोपी को प्रस्तुत किए गए हैं और यदि उसे पता चलता है कि आरोपी को प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसे दस्तावेज़ या उनमें से कोई भी, वह उसे इस प्रकार प्रस्तुत करवाएगा,"

और मजिस्ट्रेट तब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों के साक्ष्य को रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ेगा और वह ऐसे सबूतों पर और संदर्भित दस्तावेजों पर विचार करने के बाद मामले को सत्र न्यायालय को सौंप सकता है। धारा 173 में.

उपधारा 162, 173(4) और 207ए(3) का उद्देश्य आरोपी को जांच शुरू होने से पहले उसके खिलाफ मामले की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। धाराएं जांच अधिकारी पर जांच शुरू होने से पहले उन गवाहों के बयानों की प्रतियां उपलब्ध कराने का दायित्व रखती हैं, जिनकी मुकदमे में जांच की जानी है, ताकि आरोपी उन बयानों का उपयोग गवाहों से जिरह करने के लिए कर सके। जैसा कि वह बचाव करना चाहता है, और उनकी गवाही को हिला देना भी चाहता है। धारा 161(3) के तहत किसी पुलिस अधिकारी को जांच के दौरान उसके द्वारा जांचे गए गवाहों के बयान लिखित रूप में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि वह ऐसे किसी भी बयान को लिखित रूप में दर्ज करता है, तो वह उन बयानों की प्रतियां बनाने के लिए बाध्य है। अदालत में कार्यवाही शुरू होने से पहले आरोपी को उपलब्ध कराया जाता है ताकि आरोपी को उसके खिलाफ मामले का विवरण और विवरण पता चल सके और मामले को कैसे साबित किया जाना है। प्रावधान का उद्देश्य स्पष्ट रूप से अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के कब्जे में पूरी जानकारी देना है, जिस पर राज्य का मामला आधारित है, और उसके खिलाफ दिए गए बयान हैं। लेकिन जांच के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयान प्रस्तुत करने में विफलता से मुकदमा ख़राब नहीं हो सकता है। यह किसी मामले की सुनवाई करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, न ही विफलता अपने आप में एक आधार है जो दोषसिद्धि दर्ज करने की न्यायालय की शक्ति को प्रभावित करती है, यदि साक्ष्य इस तरह के पाठ्यक्रम की गारंटी देता है। जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों की प्रतियां बनाने से संबंधित प्रावधान निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके उल्लंघन को धारा 537 संहिता के लिए इसके उल्लंघन के कारण आरोपी को हुए पूर्वाग्रह के आलोक में माना जाना चाहिए। अन्य बातों के अलावा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है कि संहिता में निहित प्रावधानों के अधीन सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा पारित कोई भी निष्कर्ष, सजा या आदेश शिकायत, सम्मन में किसी त्रुटि, चूक या अनियमितता के कारण उलट या परिवर्तित नहीं किया जाएगा। , वारंट, उद्घोषणा, आदेश, निर्णय या परीक्षण से पहले या उसके दौरान या इस संहिता के तहत किसी भी जांच या अन्य कार्यवाही में, जब तक कि ऐसी त्रुटि, चूक, अनियमितता या गलत दिशा वास्तव में न्याय की विफलता का कारण न बनी हो। स्पष्टीकरण – धारा 537 में यह प्रावधान है कि यह निर्धारित करने में कि क्या इस संहिता के तहत किसी कार्यवाही में कोई त्रुटि, चूक या अनियमितता न्याय की विफलता का कारण बनी है, न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि क्या आपत्ति पहले चरण में उठाई जा सकती थी और उठायी जानी चाहिए थी। कार्यवाही.

वर्तमान मामले में कपूराराम द्वारा तैयार किए गए गवाहों के बयान अभियुक्तों को अपराध की कार्यवाही शुरू होने से पहले दिए गए थे। धारा 161(3) के तहत विधिवत दर्ज किए गए उन बयानों पर भरोसा करते हुए, गवाहों से जिरह करने का निर्देश दिया गया। लेकिन सत्र न्यायालय में जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि 29 सितंबर, 1960 को उन्होंने गवाहों के बयान विस्तार से दर्ज नहीं किए, बल्कि केवल कुछ बिंदु नोट किए और 30 सितंबर, 1960 को थाना बाली पहुंचकर उन्होंने गवाहों के विस्तृत बयान लिए। गवाहों की अनुपस्थिति में हेड–कांस्टेबल कपूराराम द्वारा लिखा गया था, और उसके बाद नोट्स और जोटिंग्स को नष्ट कर दिया गया था। निस्संदेह जांच अधिकारी ने गैर–जिम्मेदार और अनुचित दोनों तरह से काम किया और इस तरह आरोपी को उसके द्वारा लिखे गए "नोट्स और जोटिंग्स" के लाभ से वंचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उन एकमात्र दस्तावेजों को नष्ट कर दिया जिन्हें धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान के रूप में माना जा सकता था

और जिन्हें धारा 161 के तहत आरोपी द्वारा उपयोग करने की अनुमति है। अपीलकर्ता के वकील ने बलिराम बनाम सम्राट (1) में नागपुर उच्च न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा किया। और मगनलाल बनाम सम्राट (2) ने प्रस्तुत किया कि धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों की प्रतियां प्रदान करने में चूक कैदियों की उचित सुरक्षा और न्याय के सुरक्षित प्रशासन के लिए आवश्यक अभ्यास के मौलिक नियमों के प्रतिकूल है, और जहां आरोपी को उसकी सजा से वंचित किया गया था। जिरह के वैधानिक अधिकार और इस तरह अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही को प्रभावी ढंग से नष्ट करने के अवसर से वंचित कर दिया गया, ऐसे गवाहों के साक्ष्य जिनके बयान अभियुक्तों को प्रदान नहीं किए गए हैं, मुकदमे में अस्वीकार्य हैं। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि हमारे विचार में नागपुर उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कानून दंड प्रक्रिया संहिता की उपधारा 161 और 162 की सही व्याख्या नहीं करता है। बाद के एक मामले में, मारोती महगू बनाम सम्राट (1) में नागपुर उच्च न्यायालय ने माना कि हालांकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के तहत आरोपी को पुलिस को दिए गए पिछले बयानों का खंडन करने के उद्देश्य से उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। गवाही एक मूल्यवान अधिकार है, और जहां अभियुक्तों को प्रतियां देने में चूक से यह साबित हो जाता है कि इससे अभियुक्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, ऐसे गवाह की गवाही अत्यधिक सावधानी से प्राप्त की जानी चाहिए और न्यायालय उपयुक्त मामले में इसे अनदेखा करने का भी हकदार होगा कुल मिलाकर ऐसे साक्ष्य, लेकिन साक्ष्य अस्वीकार्य नहीं हैं और प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।

इन मामलों का निर्णय 1955 के अधिनियम 26 द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन से पहले किया गया था, लेकिन वकील द्वारा उठाए गए सवाल पर संशोधित प्रावधान से कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं आया है। 1955 में संहिता के संशोधन के बाद, यह हर मामले में जांच अधिकारी का कर्तव्य है जहां सीएच के तहत जांच की गई है। XIV को मुकदमे में परीक्षण के लिए प्रस्तावित गवाहों के बयानों की प्रतियों की अभियुक्तों को आपूर्ति करना। संशोधित होने से पहले संहिता के तहत, अनुरोध किए जाने पर न्यायालय को प्रत्येक गवाह के बयान आरोपी को उपलब्ध कराने होते थे, जब उसे परीक्षण के लिए बुलाया जाता था। धारा 207 ए और धारा 173 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन के प्रभाव पर इस न्यायालय द्वारा नारायण राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2) में विचार किया गया था और यह माना गया था कि धारा 173 (4) के प्रावधानों का पालन करने में विफलता) और धारा 207 ए(3) महज एक अनियमितता है जो मुकदमे की वैधता को प्रभावित नहीं करती है। इस प्रश्न से निपटने में यह देखा गया कि क्या धारा 207 ए की उपधारा (3) के साथ पढ़ी गई धारा 173(4) के प्रावधानों का अनुपालन करने में चूक आवश्यक रूप से पूरी कार्यवाही और मुकदमे को शून्य बना देती है:

> "इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन प्रावधानों को 1955 के संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया है, ताकि सत्र परीक्षण तक पहुंचने वाली पूछताछ के संबंध में प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके और साथ ही, पुलिस अधिकारियों को आदेश देकर आरोपी व्यक्तियों के हितों की रक्षा की जा सके। संबंधित और मजिस्ट्रेट जिनके समक्ष ऐसी कार्यवाही की जाती है, यह देखने के लिए कि आरोपी व्यक्तियों को उनके बचाव के उचित आचरण के लिए सभी जानकारी देने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। * * * *

लेकिन हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि उन प्रावधानों का अनुपालन न करने का परिणाम आवश्यक रूप से उन कार्यवाहियों और उसके बाद के परीक्षण को ख़राब करना होगा। धारा 173 की उप–धारा (4) और धारा 207 ए की उप–धारा (3) दोनों में आने वाला शब्द "करेगा", अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवल

निर्देशिका है, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी द्वारा प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने में चूक हुई है। धारा 173 को इतना दूरगामी प्रभाव डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे सहित कार्यवाही पूरी तरह से अप्रभावी हो जाए। * * * *

निश्चित रूप से, यदि किसी विशेष मामले में, आरोपी व्यक्तियों की ओर से यह दिखाया जाता है कि संबंधित पुलिस अधिकारियों या मजिस्ट्रेट की ओर से चूक, जिसके समक्ष कमिटमेंट की कार्यवाही लंबित थी, ने आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया है। न्याय के हित में, न्यायालय संहिता के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन पर जोर देकर कार्यवाही को फिर से शुरू कर सकता है।

हमारी राय में, तत्काल मामले में जिस चूक की शिकायत की गई है, उसका संहिता की धारा 162 या धारा 360 के प्रावधानों को लागू करने की चूक से अधिक दूरगामी प्रभाव नहीं होना चाहिए।"

उस मामले में न्यायालय ने पुलुकुरी कोटाय्या बनाम सम्राट(1) मामले में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया कि जब कोई मुकदमा संहिता द्वारा निर्धारित तरीके से अलग तरीके से आयोजित किया जाता है, तो मुकदमा खराब होता है। , और किसी अनियमितता को ठीक करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन यदि मुकदमा संहिता द्वारा निर्धारित तरीके से काफी हद तक आयोजित किया जाता है, लेकिन ऐसे आचरण के दौरान कुछ अनियमितता होती है, तो अनियमितता को धारा 537 के तहत ठीक किया जा सकता है, और इससे भी कम नहीं। क्योंकि अनियमितता में, जैसा कि लगभग हमेशा होता है, संहिता के एक या अधिक व्यापक प्रावधानों का उल्लंघन शामिल है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज बयानों की प्रतियां उपलब्ध कराने में विफलता के परिणाम से निपटने में, न्यायिक समिति ने पुलुकुरी कोटाय्या के मामले (1) में देखा:

> "इस धारा द्वारा किसी आरोपी व्यक्ति को दिया गया अधिकार बहुत मूल्यवान है और अक्सर अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करता है। जिरह के लिए सामग्री कितनी भी पतली क्यों न लगे, इसके संभावित प्रभाव का अनुमान लगाना मुश्किल है। उसके कई बयानों में मामूली विसंगतियां एक सच्चे गवाह को शर्मिंदा नहीं कर सकती हैं, लेकिन एक झूठे गवाह को विचलित कर सकती हैं, और उसके पूरे साक्ष्य को अंततः नष्ट कर सकती हैं और वर्तमान मामले में यह याद रखना होगा कि अभियुक्त का तर्क यह था कि अभियोजन पक्ष के गवाह झूठे गवाह थे। भारत में न्यायालयों ने हमेशा धारा 162 के प्रावधान के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता का मामला माना है। एआईआर 1945 नाग. 1 जहां गवाहों द्वारा दिए गए बयानों का रिकॉर्ड नष्ट कर दिया गया था, और 53 सभी 458, जहां न्यायालय ने अभियुक्तों को गवाहों द्वारा पुलिस को दिए गए बयानों की प्रतियां देने से इनकार कर दिया था, ऐसे उदाहरणों का हवाला देते हैं जिनमें धारा 162 के प्रावधानों का पालन करने में विफलता के कारण दोषसिद्धि रद्द कर दी गई है। हालाँकि, उनका आधिपत्य यह देखेगा कि जहाँ, उन दो मामलों की तरह, आरोपियों को कभी भी बयान उपलब्ध नहीं कराए गए, एक निष्कर्ष, जो लगभग अपरिवर्तनीय है, आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह का उत्पन्न होता है।"

अनुमान कितना भी मजबूत क्यों न हो, प्रतियां उपलब्ध कराने में विफलता अपने आप में मुकदमे को अवैध नहीं बना देगी। न्यायालय को प्रत्येक मामले में दोष की प्रकृति, मुकदमे में उठाई गई आपत्ति और उन परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए जो पूर्वाग्रह का कारण बनती हैं। पूर्वाग्रह के अनुमान की ताकत का निर्णय हमेशा प्रत्येक विशेष मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। नारायण राव का मामला

(2) उपधारा 173 और 207 ए के प्रावधानों का पालन करने में विफलता से संबंधित है, ऐसा प्रतीत होता है कि उस मामले में धारा 161 के तहत दर्ज गवाहों के बयान सत्र न्यायालय में अभियुक्तों को दिए गए थे, और कार्यवाही में अनियमितता थी उस हद तक कम किया गया। वर्तमान मामले में जिसे धारा 161(3) के तहत दर्ज किया गया बयान माना जा सकता है, वह आरोपी को कभी नहीं दिया गया। लेकिन उस संबंध में वैधानिक अधिकार से वंचित करने के परिणामों पर लागू सिद्धांत अलग नहीं है।

ट्रायल कोर्ट ने पाया कि बयानों की जो प्रतियां आरोपियों को सौंपी गईं, वे गवाहों द्वारा दिए गए बयानों का रिकॉर्ड नहीं थे, बल्कि उन्हें सब–इंस्पेक्टर हरि सिंह ने कुछ बिंदुओं पर 'जोटिंग' से लिखा था। , बयान हेड–कांस्टेबल कपूराराम द्वारा लिखे गए हैं। न्यायालय ने तब कहा:

"यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब जांच अधिकारी ने 29–9–60 को गवाहों से पूछताछ की तो हेड कांस्टेबल कपूराराम घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। इसलिए, गवाहों के बयान जो हेड कांस्टेबल कपूराराम की लिखावट में हैं, नहीं हो सके। ग्राम मुंडारा थाना, बाली में गवाहों को लिखे और पढ़े गए हैं, और इसलिए, जिन बयानों पर अभियोजन पक्ष भरोसा करता है, उन्हें कभी भी पढ़ा नहीं गया और गवाहों द्वारा सही नहीं माना गया। गवाहों के बयानों में कई भाग हैं जो दिए गए हैं बचाव पक्ष के वकील द्वारा रिकॉर्ड पर लाया गया, जिस पर चश्मदीद गवाहों और जांच अधिकारी के बयानों के बीच पूर्ण विरोधाभास है।"

लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विरोधाभास मुख्य रूप से हरपत सिंह और प्रताप सिंह की उपस्थिति के संबंध में थे, जिनके नाम गवाह गणेश द्वारा पहली सूचना में उल्लिखित किए गए थे, और जिनके खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था और कुछ मामलों का अधिक महत्व नहीं था, जैसे कि इस अपील में अपीलकर्ता नूर खान के अलावा अन्य व्यक्तियों के कार्य और आचरण। उदाहरण के लिए, प्रभु ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कहा था कि प्रभु सिंह और सोहन सिंह हमले के चश्मदीद गवाह थे। एमएसटी. मथुरा ने इस बात से इनकार किया कि उसने कहा था कि आरोपियों ने 'गणेश और प्रताप के साथ अभद्रता की और धमकी दी कि वे कुआं छोड़ दें अन्यथा वे उन्हें मार डालेंगे, और इसी तरह का खंडन सुश्री ने भी किया था। भंवरी. प्रभु के बयान में विरोधाभास कुएं से संबंधित विवादों के कारण अदालत में चल रही कुछ कार्यवाही से संबंधित है। यह निश्चित रूप से बहुत असंतोषजनक है कि हरि सिंह के समक्ष गवाहों द्वारा दिए गए बयानों के नोट्स, या 'जोटिंग', जैसा कि उन्हें कहा जाता है, अभियुक्तों को उपलब्ध नहीं थे क्योंकि वे उनके द्वारा नष्ट कर दिए गए थे और जो उन्हें उपलब्ध कराए गए थे। अभियुक्तों के पास वास्तव में वे बयान नहीं थे जिनका उपयोग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के तहत किया जा सकता था। इस असंतोषजनक स्थिति के लिए, उप. इंस्पेक्टर हरि सिंह को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. लेकिन केवल उस कारण से, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि मुकदमा अवैध था। ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा सब–इंस्पेक्टर हरि सिंह की डायरी की जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, न ही उच्च न्यायालय में कोई आपत्ति उठाई गई थी कि अभियुक्तों को नोट्स या जोटिंग उपलब्ध कराने में विफलता के कारण कोई पूर्वाग्रह था कारण होता था। हरि सिंह से उन जोटिंग्स या नोट्स की प्रकृति के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा गया – क्या वे महज़ ज्ञापन थे जिन्हें केवल लेखक ही समझ सकता था, या उन्हें दिए गए बयानों के विस्तृत नोट्स थे, जिन्हें लिखवाए जाने पर उचित आकार में व्यवस्थित किया गया था कपूराराम को. इस आपत्ति से निपटने में उच्च न्यायालय ने कहा:

"जिस तरीके से कपूराराम द्वारा पुलिस के बयान तैयार किए जाने का आरोप लगाया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, उनसे कोई मूल्य नहीं जोड़ा जा सकता है और यदि गवाह उन बयानों के कुछ हिस्सों से इनकार करता है, तो मुकदमे में उसके साक्ष्य को उस आधार पर अविश्वसनीय नहीं बनाया जा सकता है।"

उच्च न्यायालय ने उन गवाहों के साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण और विचार किया है जिन्होंने गवाही दी थी कि उन्होंने हमला देखा था और यह आश्वासन दिया गया था कि जिन गवाहों को चोटें आई थीं उनमें से चार गवाह अपराध स्थल और गवाही पर अवश्य मौजूद रहे होंगे। उनमें से तीन गवाहों को एमएसटी के साक्ष्य के आलोक में देखा जाना स्वीकार्य था। भंवरी और सुश्री मथुरा। हमने गवाहों के साक्ष्यों के उन भौतिक भागों का अध्ययन किया है, जिन पर हमारा ध्यान गया था, और बताई गई कमजोरियों के आलोक में साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच की है, विशेष रूप से हरि सिंह द्वारा किए गए नोट्स या जोटिंग्स की प्रतियों को अस्वीकार करने के बाद। हम उच्च न्यायालय से असहमत नहीं हो सकते।

सत्र न्यायाधीश ने तुलनात्मक रूप से मामूली महत्व के मामलों पर विसंगतियों को देखते हुए गवाहों की गवाही को खारिज कर दिया और क्योंकि गवाह मृतक के रिश्तेदार थे, और उन्होंने उस दूरी के बारे में बयान दिया जहां से हमला किया गया था जो सच नहीं हो सकता था। चिकित्सा साक्ष्य का प्रकाश. उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया। विशेष अनुमति वाली अपील में हमें नहीं लगता कि उच्च न्यायालय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करना उचित होगा, खासकर तब जब हमारा ध्यान उस न्यायालय के तर्क में किसी भी महत्वपूर्ण कमी की ओर आकर्षित नहीं किया गया हो। हम दोहरा सकते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के प्रावधान आरोपी को एक मूल्यवान सुरक्षा प्रदान करते हैं और इससे इनकार केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उचित हो सकता है। गवाहों के बयानों को रिकॉर्ड करने और अभियुक्तों को प्रतियों की आपूर्ति से संबंधित प्रावधान ताकि उनका उपयोग मुकदमे में प्रभावी ढंग से खुद का बचाव करने के लिए किया जा सके, आमतौर पर इसे कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और जहां परिस्थितियां ऐसी हैं कि न्यायालय उचित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों को प्रदान करने में विफलता के कारण अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है, न्यायालय को यह निर्देश देना उचित होगा कि दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाए और उचित मामले में यह निर्देश दिया जाए कि दोष को इस तरह से ठीक किया जाए। जैसा कि परिस्थितियाँ उचित हो सकती हैं। यह केवल तभी होता है जब अदालत इस बात से संतुष्ट होती है कि मामले को जिस तरीके से चलाया गया है और दोष के संबंध में आरोपी द्वारा अपनाए गए रवैये को देखते हुए, उल्लंघन के बावजूद, आरोपी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, दोषसिद्धि को बनाए रखने में उचित ठहराया जाए। यह, हमारे निर्णय में, उन मामलों में से एक है जिसमें इस तरह के मार्ग की आवश्यकता है।

नोट्स को नष्ट करने में सब–इंस्पेक्टर हरि सिंह की कार्रवाई की निंदा की जा सकती है। लेकिन उनके द्वारा रिकॉर्ड किए गए नोट्स को नष्ट करना किसी बेईमानी का नहीं बल्कि अज्ञानता का परिणाम प्रतीत होता है। फिर भी, अगर सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर हमें लगता है कि यह मानने का उचित आधार है कि अपीलकर्ता नूर खान पूर्वाग्रह से ग्रसित था क्योंकि वह उस अधिकार से वंचित था जो विधायिका ने उसे अपना बचाव करने के लिए सुनिश्चित किया था, तो हमने उसे अलग कर दिया होता। दोषसिद्धि.. हालाँकि हमने गवाहों के साक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और नूर खान के वकील द्वारा की गई आलोचना के आलोक में

इसकी जांच की है, और उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट की राय को उचित महत्व देने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। इस मामले के तथ्यों पर निष्कर्ष यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं हुआ है।

जैसा कि हमने पहले ही बताया है, ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह की दलील उच्च न्यायालय में नहीं उठाई गई है, और रिकॉर्ड की प्रतियां उपलब्ध कराने में विफलता के कारण मुकदमे की अवैधता की सामान्य दलील के अलावा हरि सिंह को दिए गए बयानों में पूर्वाग्रह की दलील के समर्थन में कोई ठोस तर्क नहीं दिया गया है।

हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसके आधार पर यह अपील विफल हो जाती है और खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

आशीष तिवारी की देखरेख में शिखा पांडे द्वारा अनुवादित।